Advanced International Journal of Multidisciplinary Research
E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 2, Issue 1, January-February 2024
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2024.v02i01.1494

भारत में मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास के बीच संबंध: एक सैद्धांतिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. इन्द्र सिंह

अर्थशास्त्र विभाग
दीक्षित कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, रामपुर (उत्तर प्रदेश)

सारांश

मुद्रास्फीति आधुनिक अर्थव्यवस्था की प्रमुख आर्थिक समस्याओं में से एक है। सामान्य रूप से मुद्रास्फीति का अर्थ अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि से है। कीमतों में वृद्धि होने पर मुद्रा की वास्तविक क्रय शक्ति कम हो जाती है और समान आय से पहले की तुलना में कम वस्तुएँ एवं सेवाएँ खरीदी जा सकती हैं। इसका प्रभाव परिवारों के उपभोग, बचत, निवेश, उत्पादन, रोजगार तथा आय-वितरण पर पड़ता है। भारत जैसे विकासशील देश में मुद्रास्फीति का महत्व और अधिक है क्योंकि परिवारों के उपभोग में खाद्य वस्तुओं की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा निम्न एवं मध्यम आय वर्ग अपनी आय का बड़ा भाग आवश्यक वस्तुओं पर खर्च करता है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य भारत में मुद्रास्फीति की प्रकृति, प्रमुख कारणों, विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों पर उसके प्रभाव तथा आर्थिक विकास के साथ उसके संबंध का सैद्धांतिक एवं द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर अध्ययन करना है। अध्ययन में भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित आधिकारिक सामग्री का आधार लिया गया है। उपलब्ध आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित सामान्य मुद्रास्फीति 2023–24 में 5.4 प्रतिशत रही, जो 2024–25 में घटकर 4.6 प्रतिशत हो गई। आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान सामान्य उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति और घटकर 1.7 प्रतिशत रही। इस अवधि में खाद्य कीमतों में नरमी ने मुद्रास्फीति को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नियंत्रित एवं स्थिर मुद्रास्फीति आर्थिक गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण बना सकती है, जबकि अत्यधिक एवं अस्थिर मुद्रास्फीति क्रय शक्ति, बचत, निवेश और उत्पादन संबंधी निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। अतः आर्थिक विकास के साथ मूल्य स्थिरता बनाए रखना भारत की आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए।

मुख्य शब्द: मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास, मूल्य स्तर, क्रय शक्ति, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, खाद्य मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति, आर्थिक वृद्धि

1. प्रस्तावना एवं अध्ययन की पृष्ठभूमि

किसी भी अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करते समय उत्पादन, रोजगार, आय और कीमतों की स्थिति का विशेष महत्व होता है। यदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन और आय बढ़ रही हो लेकिन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें उससे कहीं अधिक तेजी से बढ़ रही हों, तो आर्थिक विकास का वास्तविक लाभ सामान्य नागरिकों तक पूरी तरह नहीं पहुँच सकता। इसी कारण मुद्रास्फीति को आर्थिक विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। मूल्य स्तर में परिवर्तन परिवारों के उपभोग निर्णय, व्यवसायों के निवेश निर्णय और सरकार की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करता है। इसलिए आर्थिक वृद्धि के साथ मूल्य स्थिरता बनाए रखना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। मुद्रास्फीति का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव मुद्रा की क्रय शक्ति पर

Advanced International Journal of Multidisciplinary Research
E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 2, Issue 1, January-February 2024
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2024.v02i01.1494

पड़ता है। जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती है, तो समान आय से पहले की तुलना में कम वस्तुएँ खरीदी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी परिवार की आय में वृद्धि नहीं होती लेकिन खाद्य, ईंधन, परिवहन और शिक्षा की लागत बढ़ती रहती है, तो परिवार को अपने उपभोग में कटौती करनी पड़ सकती है। निम्न आय वाले परिवारों पर इसका प्रभाव अधिक गंभीर हो सकता है क्योंकि उनकी आय का बड़ा हिस्सा आवश्यक वस्तुओं पर खर्च होता है। इसके विपरीत उच्च आय वाले परिवारों के पास बचत और निवेश की अधिक संभावनाएँ होती हैं, जिससे वे मूल्य वृद्धि के कुछ प्रभावों को सहन कर सकते हैं। भारत में मुद्रास्फीति की प्रकृति को समझने के लिए खाद्य कीमतों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की बड़ी आबादी कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है तथा परिवारों के उपभोग में खाद्य वस्तुओं का बड़ा हिस्सा है। मौसम, मानसून, कृषि उत्पादन, भंडारण व्यवस्था, परिवहन लागत और अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियाँ खाद्य कीमतों को प्रभावित कर सकती हैं। इस कारण भारत में मुद्रास्फीति कई बार केवल मौद्रिक परिस्थितियों से नहीं बल्कि आपूर्ति संबंधी समस्याओं से भी उत्पन्न होती है। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार भारत में सामान्य उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 2023–24 में 5.4 प्रतिशत थी, जो 2024–25 में घटकर 4.6 प्रतिशत हुई। आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान यह दर और घटकर 1.7 प्रतिशत रही। इन आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि हाल के वर्षों में भारत में मूल्य दबाव में कमी आई है। फिर भी मुद्रास्फीति की प्रकृति, उसके कारणों और आर्थिक विकास पर उसके प्रभाव का अध्ययन आवश्यक है क्योंकि कीमतों में अचानक वृद्धि भविष्य में फिर से आर्थिक चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकती है।

2. मुद्रास्फीति : अर्थ, अवधारणा एवं सैद्धांतिक आधार

मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि से है। किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि को मुद्रास्फीति नहीं कहा जाता। उदाहरण के लिए यदि केवल किसी एक सब्जी की कीमत बढ़ती है तो यह आवश्यक नहीं कि पूरी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ गई हो। मुद्रास्फीति तब मानी जाती है जब अनेक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में व्यापक तथा निरंतर वृद्धि होती है। इस स्थिति में मुद्रा की वास्तविक क्रय शक्ति घटने लगती है। मुद्रास्फीति को समझने के लिए मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों का अध्ययन आवश्यक है। मांग आधारित मुद्रास्फीति तब उत्पन्न हो सकती है जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग उपलब्ध आपूर्ति से अधिक हो जाए। इसके विपरीत लागत आधारित मुद्रास्फीति तब उत्पन्न हो सकती है जब उत्पादन की लागत बढ़ जाए। कच्चे माल, ईंधन, परिवहन, मजदूरी और अन्य उत्पादन लागतों में वृद्धि होने पर उत्पादक अपनी कीमतें बढ़ा सकते हैं। भारत में दोनों प्रकार के मूल्य दबाव अलग-अलग समय पर देखे जा सकते हैं। संरचनात्मक मुद्रास्फीति भी भारत जैसे विकासशील देश के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कृषि उत्पादन पर्याप्त नहीं है, भंडारण सुविधाएँ सीमित हैं, परिवहन व्यवस्था कमजोर है अथवा बाजारों में आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है, तो वस्तुओं की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। इससे कीमतों में वृद्धि हो सकती है। इसलिए भारत में मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए केवल ब्याज दरों में परिवर्तन पर्याप्त नहीं है। कृषि उत्पादन, भंडारण, परिवहन और बाजार व्यवस्था में सुधार भी आवश्यक है। मुद्रास्फीति के मापन के लिए भारत में मुख्य रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। यह सामान्य उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग भी किया जाता है, जो थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को दर्शाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आम नागरिक के जीवन-यापन की लागत को समझने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

3. भारत में मुद्रास्फीति की वर्तमान स्थिति एवं प्रवृत्तियाँ

भारत में मुद्रास्फीति की स्थिति पिछले कुछ वर्षों में कई उतार-चढ़ाव से गुजरी है। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा कीमतों में परिवर्तन, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, कृषि उत्पादन में उतार-चढ़ाव तथा घरेलू मांग की स्थिति ने भारत की मुद्रास्फीति को प्रभावित किया है। विशेष रूप से खाद्य वस्तुओं की कीमतों में अचानक वृद्धि का प्रभाव समग्र मुद्रास्फीति पर दिखाई देता है।

Advanced International Journal of Multidisciplinary Research
E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 2, Issue 1, January-February 2024
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2024.v02i01.1494

तालिका 1 : भारत में सामान्य उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति

अवधि	सामान्य मुद्रास्फीति
2023–24	5.4%
2024–25	4.6%
2025–26 अप्रैल–दिसंबर	1.7%

स्रोत: भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26।

तालिका से स्पष्ट है कि भारत में सामान्य मुद्रास्फीति की गति में उल्लेखनीय कमी आई है। 2023–24 में सामान्य मुद्रास्फीति 5.4 प्रतिशत थी, जो 2024–25 में घटकर 4.6 प्रतिशत हुई। इस प्रकार एक वर्ष में सामान्य मुद्रास्फीति में 0.8 प्रतिशत अंक की कमी दिखाई देती है। यह परिवर्तन अर्थव्यवस्था में मूल्य दबाव के कम होने का संकेत देता है। 2025–26 के अप्रैल से दिसंबर की अवधि में सामान्य मुद्रास्फीति 1.7 प्रतिशत तक पहुँच गई। आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार इस कमी में खाद्य कीमतों में नरमी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कृषि उत्पादन की बेहतर स्थिति और कुछ प्रमुख खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कमी के कारण उपभोक्ता स्तर पर मूल्य दबाव कम हुआ। मुद्रास्फीति में कमी का सकारात्मक प्रभाव परिवारों की वास्तविक क्रय शक्ति पर पड़ सकता है। यदि आय में वृद्धि बनी रहती है और कीमतों की वृद्धि की गति कम हो जाती है, तो परिवार अपनी आय से अधिक वस्तुएँ और सेवाएँ खरीद सकते हैं। इससे उपभोग को समर्थन मिल सकता है। इसी प्रकार व्यवसायों के लिए भी स्थिर कीमतें निवेश और उत्पादन संबंधी निर्णयों में अनिश्चितता को कम कर सकती हैं। फिर भी बहुत कम मुद्रास्फीति को स्वतः सकारात्मक नहीं माना जाना चाहिए। यदि मुद्रास्फीति में कमी कमजोर मांग और आर्थिक गतिविधि में गिरावट के कारण हो, तो यह अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का कारण हो सकती है। इसलिए मुद्रास्फीति का विश्लेषण उत्पादन, रोजगार, उपभोग और निवेश जैसे अन्य आर्थिक संकेतकों के साथ किया जाना चाहिए।

4. खाद्य मुद्रास्फीति एवं भारत की अर्थव्यवस्था

भारत में खाद्य मुद्रास्फीति का विशेष महत्व है क्योंकि भारतीय परिवारों के घरेलू व्यय में खाद्य वस्तुओं का बड़ा हिस्सा होता है। अनाज, दालें, सब्जियाँ, फल, दूध, खाद्य तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि सीधे परिवारों के मासिक बजट को प्रभावित करती है। इसलिए खाद्य कीमतों में होने वाला परिवर्तन सामान्य उपभोक्ता के लिए मुद्रास्फीति के अनुभव को काफी हद तक निर्धारित करता है। खाद्य मुद्रास्फीति के अनेक कारण हो सकते हैं। कृषि उत्पादन में कमी, मानसून में असामान्यता, सूखा, बाढ़, तापमान में वृद्धि, कीट प्रकोप तथा अन्य प्राकृतिक परिस्थितियाँ खाद्य आपूर्ति को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा भंडारण, परिवहन और वितरण व्यवस्था में समस्याएँ होने पर भी उत्पादन पर्याप्त होने के बावजूद उपभोक्ता तक वस्तुएँ उचित कीमत पर नहीं पहुँच सकतीं। भारत में खाद्य मुद्रास्फीति का प्रभाव निम्न आय वर्ग पर विशेष रूप से अधिक पड़ता है। ऐसे परिवार अपनी आय का बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च करते हैं। यदि भोजन की कीमत बढ़ती है, तो उनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य, बचत या अन्य आवश्यकताओं के लिए कम धन बचता है। इस कारण खाद्य मुद्रास्फीति केवल आर्थिक समस्या नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण की समस्या भी बन जाती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय नरमी आई और इसने सामान्य मुद्रास्फीति को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में मूल्य स्थिरता के लिए कृषि उत्पादन और खाद्य आपूर्ति व्यवस्था का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार को कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ भंडारण सुविधाओं का विस्तार, परिवहन व्यवस्था में सुधार, कृषि बाजारों को अधिक कुशल बनाना तथा आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए। केवल मौद्रिक

Advanced International Journal of Multidisciplinary Research
E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 2, Issue 1, January-February 2024
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2024.v02i01.1494

नीति के माध्यम से खाद्य कीमतों को नियंत्रित करना कठिन हो सकता है क्योंकि इसका मूल कारण कई बार आपूर्ति पक्ष में होता है।

5. मुद्रास्फीति का क्रय शक्ति, बचत एवं निवेश पर प्रभाव

मुद्रास्फीति का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव लोगों की वास्तविक आय और क्रय शक्ति पर पड़ता है। जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें आय की तुलना में तेजी से बढ़ती हैं, तो व्यक्ति की वास्तविक आय कम हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति की मुद्रा की मात्रा समान रहने के बावजूद उसकी खरीद क्षमता घट जाती है। यह प्रभाव विशेष रूप से वेतनभोगी और निश्चित आय वाले परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के रूप में यदि किसी परिवार की मासिक आय 40,000 रुपये है और उसकी आय में कोई वृद्धि नहीं होती, लेकिन खाद्य, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं, तो परिवार को अपने खर्चों में परिवर्तन करना पड़ेगा। वह गैर-जरूरी वस्तुओं की खरीद कम कर सकता है, बचत घटा सकता है या ऋण पर निर्भर हो सकता है। इस प्रकार उच्च मुद्रास्फीति घरेलू आर्थिक सुरक्षा को कमजोर कर सकती है। मुद्रास्फीति बचत के वास्तविक मूल्य को भी प्रभावित करती है। यदि किसी व्यक्ति ने धन बचाकर रखा है और वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, तो भविष्य में उसी बचत से कम वस्तुएँ खरीदी जा सकेंगी। यदि बचत पर मिलने वाला प्रतिफल मुद्रास्फीति की दर से कम है, तो वास्तविक रूप से बचत का मूल्य घट सकता है। इस कारण स्थिर मुद्रास्फीति वित्तीय बचत और दीर्घकालीन आर्थिक योजना के लिए अधिक अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। निवेश पर भी मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ता है। यदि कच्चे माल, मजदूरी, परिवहन और ऊर्जा की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव होता रहे, तो व्यवसायों के लिए भविष्य की लागत का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। इससे निवेश संबंधी अनिश्चितता बढ़ सकती है। दूसरी ओर नियंत्रित मुद्रास्फीति व्यवसायों को अपेक्षाकृत स्थिर वातावरण देती है, जिससे वे दीर्घकालीन निवेश और उत्पादन विस्तार की योजना बना सकते हैं। इस प्रकार मुद्रास्फीति का प्रभाव केवल उपभोक्ता बाजार तक सीमित नहीं रहता। यह परिवारों की आय, बचत व्यवहार, निवेश निर्णय और भविष्य की आर्थिक योजना को भी प्रभावित करती है। इसलिए मूल्य स्थिरता आर्थिक विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों में से एक है।

6. मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास के बीच संबंध

मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास के बीच संबंध सरल और एक-दिशीय नहीं है। आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के दौरान मांग बढ़ने से कीमतों में कुछ वृद्धि हो सकती है। यदि उत्पादन और रोजगार भी साथ-साथ बढ़ रहे हों, तो सीमित मुद्रास्फीति आर्थिक गतिविधियों के साथ रह सकती है। लेकिन यदि कीमतों में वृद्धि उत्पादन की वृद्धि से बहुत अधिक हो जाए, तो वास्तविक आय और क्रय शक्ति प्रभावित हो सकती है।

तालिका 2: मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास के संभावित प्रभाव

मुद्रास्फीति की स्थिति	उपभोग पर प्रभाव	निवेश पर प्रभाव	आर्थिक विकास पर संभावित प्रभाव
नियंत्रित	सामान्य या सकारात्मक	अपेक्षाकृत अनुकूल	सकारात्मक
मध्यम लेकिन अस्थिर	अनिश्चित	सावधानी बढ़ती है	मिश्रित
अत्यधिक	क्रय शक्ति में कमी	निवेश में अनिश्चितता	नकारात्मक
बहुत कम एवं मांग कमजोर	मांग कमजोर हो सकती है	निवेश घट सकता है	नकारात्मक हो सकता है

तालिका से स्पष्ट है कि मुद्रास्फीति का आर्थिक विकास पर प्रभाव उसकी मात्रा और स्थिरता पर निर्भर करता है। नियंत्रित मुद्रास्फीति के वातावरण में व्यवसाय भविष्य की कीमतों का अपेक्षाकृत बेहतर अनुमान लगा सकते हैं। परिवार भी अपनी आय

Advanced International Journal of Multidisciplinary Research
E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 2, Issue 1, January-February 2024
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2024.v02i01.1494

और व्यय की योजना अधिक स्थिरता के साथ बना सकते हैं। अत्यधिक मुद्रास्फीति की स्थिति में परिवारों की वास्तविक आय प्रभावित हो सकती है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेज वृद्धि होने पर उपभोग संरचना बदल सकती है। परिवार गैर-जरूरी वस्तुओं पर खर्च कम कर सकते हैं और बचत को प्रभावित कर सकते हैं। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो घरेलू मांग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। निवेश के लिए भी मूल्य स्थिरता महत्वपूर्ण है। किसी उद्योग की परियोजना कई वर्षों के लिए होती है। यदि भविष्य की लागत और बिक्री कीमतों में अत्यधिक अनिश्चितता हो, तो निवेशक नए निवेश को टाल सकता है। इससे पूँजी निर्माण और भविष्य की उत्पादन क्षमता प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर अत्यधिक कम मुद्रास्फीति भी हमेशा अच्छी स्थिति नहीं है। यदि कीमतों में वृद्धि बहुत कम होने का कारण कमजोर मांग और आर्थिक गतिविधियों में गिरावट है, तो उत्पादन और रोजगार प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए नीति निर्माताओं को मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

7. मुद्रास्फीति और रोजगार, आय असमानता तथा सामाजिक कल्याण

मुद्रास्फीति और रोजगार का संबंध भी महत्वपूर्ण है। कुछ परिस्थितियों में बढ़ती मांग उत्पादन और रोजगार को बढ़ा सकती है तथा इसके साथ कीमतों में कुछ वृद्धि हो सकती है। लेकिन यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक और अस्थिर हो जाती है, तो उत्पादन लागत बढ़ सकती है और व्यवसायों के लिए उत्पादन संबंधी निर्णय कठिन हो सकते हैं। इससे रोजगार सृजन की गति प्रभावित हो सकती है। आय असमानता पर मुद्रास्फीति का प्रभाव विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग होता है। निम्न आय वर्ग अपनी आय का बड़ा हिस्सा भोजन, ईंधन और आवश्यक वस्तुओं पर खर्च करता है। इसलिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव उनकी वास्तविक आय पर अधिक पड़ सकता है। उच्च आय वर्ग के पास बचत, निवेश और अन्य परिसंपत्तियाँ होती हैं, जिससे वे मुद्रास्फीति के कुछ प्रभावों का सामना अधिक आसानी से कर सकते हैं। निश्चित आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए मुद्रास्फीति विशेष चुनौती हो सकती है। यदि वेतन या पेंशन में वृद्धि कीमतों की वृद्धि की गति से कम है, तो उनकी वास्तविक आय कम हो जाती है। इसके विपरीत कुछ उत्पादकों को बढ़ती कीमतों से अधिक आय प्राप्त हो सकती है, विशेषकर जब उनके उत्पादों की कीमत उत्पादन लागत से अधिक तेजी से बढ़ती है। मुद्रास्फीति का सामाजिक कल्याण पर भी प्रभाव पड़ता है। जब आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, तो परिवारों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर खर्च कम करना पड़ सकता है। दीर्घकाल में इसका प्रभाव मानव पूँजी पर पड़ सकता है। इसलिए मुद्रास्फीति नियंत्रण को केवल मूल्य नीति नहीं बल्कि सामाजिक विकास की नीति के रूप में भी देखा जाना चाहिए।

8. मुद्रास्फीति नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक एवं सरकार की भूमिका

भारत में मुद्रास्फीति नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका है। मौद्रिक नीति के माध्यम से ब्याज दर, तरलता और ऋण की उपलब्धता को प्रभावित किया जाता है। जब मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो केंद्रीय बैंक मौद्रिक परिस्थितियों को अपेक्षाकृत सख्त कर सकता है ताकि अत्यधिक मांग पर नियंत्रण रखा जा सके। ब्याज दरों में वृद्धि से ऋण लेना महँगा हो सकता है। इससे उपभोग और निवेश की कुछ मांग कम हो सकती है तथा अर्थव्यवस्था में मूल्य दबाव घट सकता है। लेकिन ब्याज दरों का अत्यधिक उपयोग आर्थिक वृद्धि को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए मौद्रिक नीति में मूल्य स्थिरता और आर्थिक गतिविधि के बीच संतुलन आवश्यक है। सरकार की राजकोषीय नीति भी मुद्रास्फीति नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारी व्यय, कर नीति, सब्सिडी, खाद्य भंडारण और आयात-निर्यात नीति वस्तुओं की मांग और आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है। खाद्य कीमतों में अचानक वृद्धि होने पर सरकार भंडार से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ा सकती है या आयात नीति में परिवर्तन कर सकती है। भारत में मुद्रास्फीति का एक बड़ा भाग आपूर्ति संबंधी कारणों से भी प्रभावित होता है। इसलिए केवल मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति का स्थायी समाधान संभव नहीं है। कृषि उत्पादन, भंडारण, परिवहन, ऊर्जा और वितरण व्यवस्था में सुधार भी आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति तथा सरकार की राजकोषीय एवं आपूर्ति संबंधी नीतियों

Advanced International Journal of Multidisciplinary Research
E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 2, Issue 1, January-February 2024
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2024.v02i01.1494

के बीच बेहतर समन्वय से मूल्य स्थिरता को अधिक प्रभावी ढंग से बनाए रखा जा सकता है। इसके साथ कमजोर आय वर्ग की क्रय शक्ति की रक्षा करना भी आवश्यक है।

9. भारत में मुद्रास्फीति के द्वितीयक आँकड़ों का विश्लेषण

तालिका 3: भारत में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति

अवधि	सामान्य मुद्रास्फीति
2023–24	5.4%
2024–25	4.6%
2025–26 अप्रैल–दिसंबर	1.7%

स्रोत: भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26।

तालिका के आँकड़ों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि 2023–24 से 2025–26 के दौरान भारत में सामान्य मुद्रास्फीति की गति में लगातार कमी दिखाई दी। 2023–24 में मुद्रास्फीति 5.4 प्रतिशत थी। 2024–25 में यह घटकर 4.6 प्रतिशत हुई और 2025–26 के अप्रैल से दिसंबर की अवधि में 1.7 प्रतिशत तक पहुँच गई। यह परिवर्तन मूल्य दबाव में उल्लेखनीय कमी को दर्शाता है। 2024–25 में 0.8 प्रतिशत अंक की कमी बताती है कि पिछले वर्ष की तुलना में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि की गति कम हुई। यह परिवारों के लिए सकारात्मक स्थिति हो सकती है, विशेषकर तब जब उनकी आय में भी वृद्धि हो रही हो। कीमतों की कम वृद्धि से परिवार अपनी आय का अधिक हिस्सा बचत या अन्य आवश्यकताओं पर खर्च कर सकते हैं। 2025–26 के अप्रैल से दिसंबर की अवधि में 1.7 प्रतिशत की मुद्रास्फीति और अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाती है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार खाद्य कीमतों में नरमी इसका प्रमुख कारण रही। खाद्य कीमतों में कमी का सीधा लाभ परिवारों को मिलता है क्योंकि भोजन घरेलू व्यय का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालाँकि इस आँकड़े को सावधानीपूर्वक समझना आवश्यक है। कम मुद्रास्फीति का अर्थ यह नहीं है कि सभी वस्तुओं की कीमतें कम हो गई हैं। इसका अर्थ केवल यह है कि कीमतों में वृद्धि की गति कम हुई है। यदि किसी वस्तु की कीमत पहले ही काफी बढ़ चुकी है और उसके बाद उसकी कीमत स्थिर रहती है, तो मुद्रास्फीति कम हो सकती है लेकिन वस्तु की कीमत पहले के स्तर पर वापस नहीं आती। इसलिए मुद्रास्फीति का विश्लेषण करते समय वर्तमान कीमत और कीमतों की वृद्धि दर के बीच अंतर समझना आवश्यक है। भारत के संदर्भ में यह अंतर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि खाद्य वस्तुओं की कीमतों में थोड़े समय में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं।

10. आर्थिक विकास और मूल्य स्थिरता के बीच संतुलन

आर्थिक विकास का उद्देश्य केवल राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाना नहीं है। आर्थिक विकास का वास्तविक उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार, रोजगार में वृद्धि, आय के बेहतर वितरण और सामाजिक कल्याण को बढ़ाना भी है। यदि उत्पादन बढ़ता है लेकिन कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, तो आर्थिक वृद्धि का वास्तविक लाभ कम हो सकता है। मूल्य स्थिरता निवेश के लिए भी आवश्यक है। निवेशक दीर्घकालीन परियोजनाओं में धन लगाते समय भविष्य की लागत और आय का अनुमान लगाते हैं। यदि कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता हो, तो निवेश का जोखिम बढ़ सकता है। इसके विपरीत अपेक्षाकृत स्थिर कीमतें निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती हैं। मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि के बीच उचित संतुलन बनाना नीति निर्माताओं के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। बहुत अधिक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक सख्त मौद्रिक नीति अपनाने से मांग और निवेश प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी ओर यदि मूल्य वृद्धि को लंबे समय तक अनदेखा किया जाए, तो वास्तविक आय और आर्थिक स्थिरता पर

Advanced International Journal of Multidisciplinary Research
E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 2, Issue 1, January-February 2024
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2024.v02i01.1494

नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भारत जैसे विकासशील देश में मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक वृद्धि बनाए रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। देश को बुनियादी ढाँचे, उद्योग, कृषि, रोजगार और मानव पूँजी में बड़े निवेश की आवश्यकता है। इसलिए आर्थिक नीति ऐसी होनी चाहिए जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखते हुए उत्पादन और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाए।

11. प्रमुख चुनौतियाँ एवं नीतिगत सुझाव

भारत में मुद्रास्फीति नियंत्रण की पहली बड़ी चुनौती खाद्य कीमतों की अस्थिरता है। कृषि उत्पादन मौसम पर निर्भर करता है और मौसम में बदलाव उत्पादन तथा कीमतों दोनों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए कृषि उत्पादकता, सिंचाई, भंडारण और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक है। दूसरी चुनौती ऊर्जा कीमतों से संबंधित है। ईंधन और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव केवल परिवहन पर नहीं बल्कि लगभग सभी वस्तुओं की उत्पादन और वितरण लागत पर पड़ता है। इसलिए ऊर्जा सुरक्षा तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विस्तार दीर्घकाल में मूल्य स्थिरता में सहायता कर सकता है। तीसरी चुनौती वैश्विक आर्थिक परिस्थितियाँ हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन भारत की घरेलू कीमतों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए बाहरी झटकों से बचने के लिए पर्याप्त रणनीतिक भंडार और विविधीकृत आपूर्ति व्यवस्था आवश्यक है। चौथी चुनौती निम्न आय वर्ग की क्रय शक्ति की रक्षा करना है। मुद्रास्फीति की स्थिति में लक्षित सहायता, खाद्य सुरक्षा और आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। नीतिगत रूप से भारत को कृषि उत्पादन बढ़ाने, भंडारण क्षमता विकसित करने, परिवहन एवं वितरण व्यवस्था मजबूत करने, मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति में समन्वय स्थापित करने तथा कमजोर वर्गों की क्रय शक्ति की रक्षा करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ दीर्घकालीन निवेश और उत्पादन क्षमता बढ़ाने की नीतियाँ भी आवश्यक हैं।

12. निष्कर्ष

भारत में मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास के बीच संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियंत्रित और स्थिर मुद्रास्फीति सामान्य आर्थिक गतिविधियों के साथ रह सकती है, लेकिन अत्यधिक और अस्थिर मुद्रास्फीति परिवारों की क्रय शक्ति, बचत, निवेश, उत्पादन और रोजगार को प्रभावित कर सकती है। इसलिए आर्थिक विकास को स्थायी और समावेशी बनाने के लिए मूल्य स्थिरता को महत्वपूर्ण स्थान देना आवश्यक है। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार भारत में सामान्य उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 2023–24 में 5.4 प्रतिशत थी, जो 2024–25 में घटकर 4.6 प्रतिशत हुई। 2025–26 के अप्रैल से दिसंबर की अवधि में सामान्य मुद्रास्फीति 1.7 प्रतिशत रही और खाद्य कीमतों में नरमी ने इस कमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुद्रास्फीति में कमी परिवारों की वास्तविक क्रय शक्ति के लिए सकारात्मक हो सकती है। यदि आय स्थिर या बढ़ती रहे और कीमतों की वृद्धि की गति कम हो, तो परिवार अपनी आय से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कर सकते हैं। इससे घरेलू मांग को समर्थन मिल सकता है। स्थिर कीमतें व्यवसायों के लिए निवेश और उत्पादन संबंधी निर्णयों को भी अधिक निश्चित बना सकती हैं। हालाँकि मुद्रास्फीति की अत्यधिक कमी को भी स्वतः सकारात्मक नहीं माना जाना चाहिए। यदि कम मुद्रास्फीति कमजोर मांग और आर्थिक गतिविधि में कमी के कारण उत्पन्न होती है, तो इसका प्रभाव उत्पादन और रोजगार पर पड़ सकता है। इसलिए मुद्रास्फीति का विश्लेषण आर्थिक वृद्धि, रोजगार, उपभोग और निवेश के साथ संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। भारत के लिए मूल्य स्थिरता बनाए रखना विशेष रूप से आवश्यक है क्योंकि देश की बड़ी आबादी निम्न और मध्यम आय वर्ग से संबंधित है। खाद्य और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेज वृद्धि इन परिवारों की वास्तविक आय पर अधिक प्रभाव डालती है। इसलिए मुद्रास्फीति नियंत्रण को आर्थिक नीति के साथ-साथ सामाजिक कल्याण की नीति के रूप में भी देखा जाना चाहिए। अंततः यह कहा जा सकता है कि भारत के लिए ऐसी आर्थिक नीति आवश्यक है जिसमें **मूल्य स्थिरता, आर्थिक वृद्धि, रोजगार और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन** स्थापित किया जाए। कृषि उत्पादन और आपूर्ति व्यवस्था में सुधार, प्रभावी मौद्रिक नीति, विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति, ऊर्जा

Advanced International Journal of Multidisciplinary Research
E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 2, Issue 1, January-February 2024
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2024.v02i01.1494

सुरक्षा तथा कमजोर वर्गों की क्रय शक्ति की रक्षा के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखते हुए आर्थिक विकास को गति दी जा सकती है।

13. अध्ययन की सीमाएँ एवं भविष्य के अध्ययन की संभावनाएँ

प्रस्तुत अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों और सैद्धांतिक सामग्री पर आधारित है। इसमें प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है। विभिन्न स्रोतों में मुद्रास्फीति की गणना अलग-अलग सूचकांकों और पद्धतियों के आधार पर की जा सकती है, इसलिए आँकड़ों की तुलना करते समय संबंधित सूचकांक और समयावधि को ध्यान में रखना आवश्यक है। मुद्रास्फीति अनेक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कारकों से प्रभावित होती है। कृषि उत्पादन, मौसम, ऊर्जा कीमतें, वैश्विक बाजार, विनिमय दर, आपूर्ति श्रृंखला तथा मौद्रिक नीति सभी इसका प्रभाव निर्धारित कर सकते हैं। इसलिए केवल मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि के दो आँकड़ों के आधार पर प्रत्यक्ष कारणात्मक संबंध स्थापित करना उचित नहीं होगा। भविष्य में विभिन्न राज्यों में मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। खाद्य मुद्रास्फीति का ग्रामीण और नगरीय परिवारों की वास्तविक आय पर प्रभाव, मुद्रास्फीति का महिला परिवार सदस्यों पर प्रभाव, निम्न आय वर्ग की उपभोग संरचना तथा मुद्रास्फीति और रोजगार के संबंध पर भी विस्तृत अध्ययन किया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संबंधी आँकड़े। (mospi.gov.in)
2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय। आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26। (indiabudget.gov.in)
3. भारतीय रिजर्व बैंक। मौद्रिक नीति एवं मुद्रास्फीति संबंधी प्रतिवेदन। (rbi.org.in)
4. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय। आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25।
5. भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। राष्ट्रीय आय एवं मूल्य संबंधी सांख्यिकी।
6. भारतीय रिजर्व बैंक। वार्षिक प्रतिवेदन।
7. नीति आयोग। भारत में मूल्य स्थिरता एवं आर्थिक विकास संबंधी अध्ययन।